Public Expenditure and Full Employment & Economic Stability

सरकारी व्यय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाला व्यय को कहते है। वर्तमान समय में सभी देशों में सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है। सरकारी व्यय का अधिकाधिक आश्रय इसलिए किया जाता है ताकि इससे देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया जा सके। सार्वजनिक व्यय किसी भी देश के उत्पादन, धन के वितरण तथा रोजगार को प्रभावित करती है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की मान्यता को स्वीकार कर लिया था इसलिए रोजगार में वृद्धि के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत महसूस नहीं हुआ।

लेकिन 1930 की महामंदी ने पूंजीवादी देशों में व्यापक बेरोजगारी फैला दिया। ब्याज में परिवर्तन से विनियोग पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज (r) में कमी करने से विनियोग (I) में वृद्धि होता है —

$$I = f(r) \quad ; \quad \frac{dI}{dr} < 0$$

महामंदी के समय ब्याज दर में बहुत कमी की गई किन्तु मौद्रिक नीति के द्वारा रोजगार एवं विनियोग में वृद्धि नहीं हो पाई।

J.M. Keynes का मत था कि मंदी काल में बेरोजगारी की समस्या मौद्रिक नीति से दूर हो सकती है। ~~किन्तु~~ ब्याज दर को घटा कर Negative ब्याज दर (−r) कर देना चाहिए तभी पूर्ण रोजगार के स्तर पर बचत एवं विनियोग एक बराबर हो सकेगा। Don Patinkin + Keynes

Scanned with OKEN Scanner

के इस विचार को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत

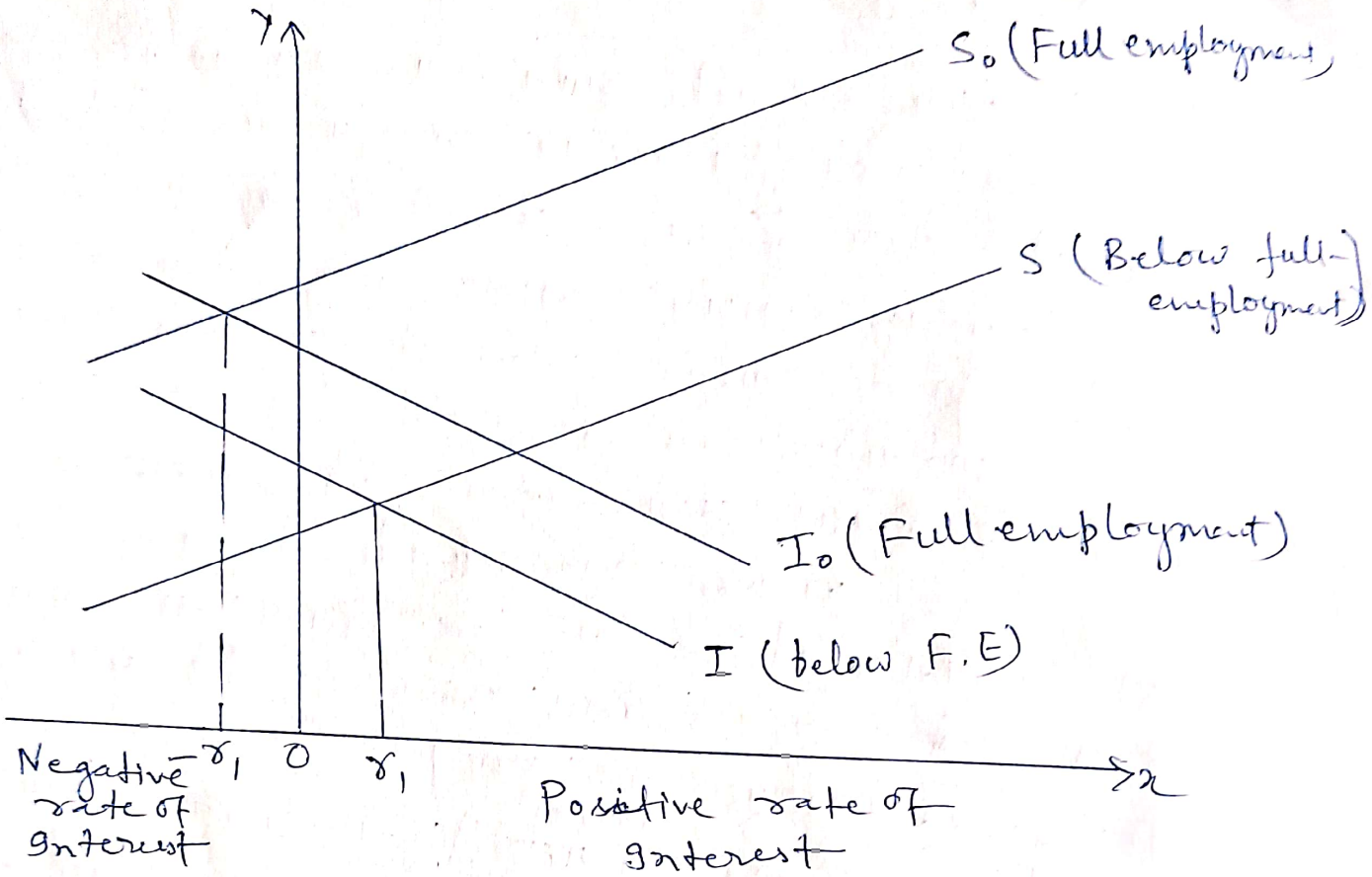

Keynes ने आज परिवर्तन से पूर्ण रोजगार पाना मंदी काल में असंभव बतलाया है। चित्र से स्पष्ट है कि बचत विनियोग की तुलना में अधिक Interest elastic है।

Keynes ने पूर्ण रोजगार की प्राप्ती के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत पर बल दिया। Laissez faire की समाप्ती तथा State Intervention की आवश्यकता को पूंजीवादी देशों में प्रकाश में लाया।

सार्वजनिक व्यय के द्वारा मंदी को दूर कर पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार वृद्धि के लिए सरकार को स्वयं विनियोग करना होगा। सरकारी व्यय निम्नलिखित तरीकों से करके पर पूर्ण रोजगार की प्राप्ती हो सकती है —

सार्वजनिक निर्माण कार्य

सरकार सार्वजनिक निर्माण की कुछ विशेष योजनाओं को चालू कर सकती है जैसे कि सड़कों, बांधों तथा पुलों आदि के निर्माण का कार्य। ऐसी योजनाओं से काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाता है। जिससे उनकी क्रयशक्ति बढ़ जाती है। क्रयशक्ति बढ़ने से देश में वस्तुओं की कुल मांग में भी वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप अन्य उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते है। सार्वजनिक निर्माण कार्य की योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च मुफ्त सहायता देने के खर्च से श्रेष्ठ होता है क्योंकि एक तो इससे अनेक सार्वजनिक निर्माण कार्य संपन्न हो जाते है जो नैतिक तथा दूसरे मुफ्त सहायता की योजनाओं से गिरावट होती है इसकी की संभावना नहीं रहती है। सार्वजनिक व्यय उन योजनाओं पर किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक महत्व के हो।

पेंशन तथा लाभ

पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी को दूर कर पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए बेरोजगारी पेंशन अथवा लाभ को सार्वजनिक व्यय के द्वारा जनता को दिया जाना चाहिए। पेंशन एवं लाभ एक ऐसी निधि से दिये जाते है जो कि विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इस निधि का निर्माण कर्मचारियों, मालिकों तथा सरकार के सम्मिलित अंशदान द्वारा होता है अतः कर्मचारी इन निधियों से मिलने वाली अनुदानों को अपने अधिकार

के रूप में स्वीकार कर लेते है। इस संदर्भ में एक आशंका बनी रहती है कि पैसा का पूरा मुद्रा जनता द्वारा व्यय किया गया या नहीं।

व्यवसायहीन लोगों की सहायता

व्यवसायहीन लोगों की सहायता से मतलब यह है कि सरकार लोगों से कोई भी काम कराये बिना ही उन्हें सहायता अनुदान (Relief grant) देती है। इस व्यय को स्थानान्तरण व्यय (Transfer Expenditure) भी कहा जाता है। क्योंकि यह धन वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के रूप में नहीं दिया जाता बल्कि धन का केवल स्थानान्तरण मात्र होता है। रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसे खर्चों का लाभ यह है कि इनके द्वारा दिया हुआ लगभग सारा ही धन प्राप्त कर्ताओं द्वारा पुनः खर्च कर दिया जाता है चूंकि ऐसी सहायता साधारणतः अत्यंत निर्धन व्यक्तियों को ही दी जाती है और चूंकि प्राप्तकर्ताओं को यह विश्वास रहता है कि जबतक वे बेरोजगार रहेंगे उन्हें ऐसी सहायता मिलती रहेगी, अतः सामान्यतः वे इस प्रकार प्राप्त सहायता का अधिकांश भाग अपनी उपभोग की आवश्यकताओं पर खर्च कर देते है। इस सबके बावजूद, ऐसे खर्चों में कुछ कमियाँ भी पाई जाती है। ऐसे खर्चे प्राप्त-कर्ताओं को प्रायः अरुचिकर लगते है क्योंकि इनमें दान या खैरात की गन्ध पाई जाती है। इससे प्राप्त-कर्ताओं का नैतिक स्तर भी गिर जाता है। इसलिए वृद्धों, अपाहिजों तथा विधवाओं।

को छोड़कर अन्य लोगों को इसप्रकार का लाभ सार्वजनिक व्यय से नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।

Keynes ने अपनी पुस्तक "The General theory of Employment, Interest and money" में लिखा है कि रोजगार का निर्धारण effective demand के द्वारा होता है और effective demand का निर्धारण Aggregate demand function तथा Aggregate supply function के द्वारा होता है —

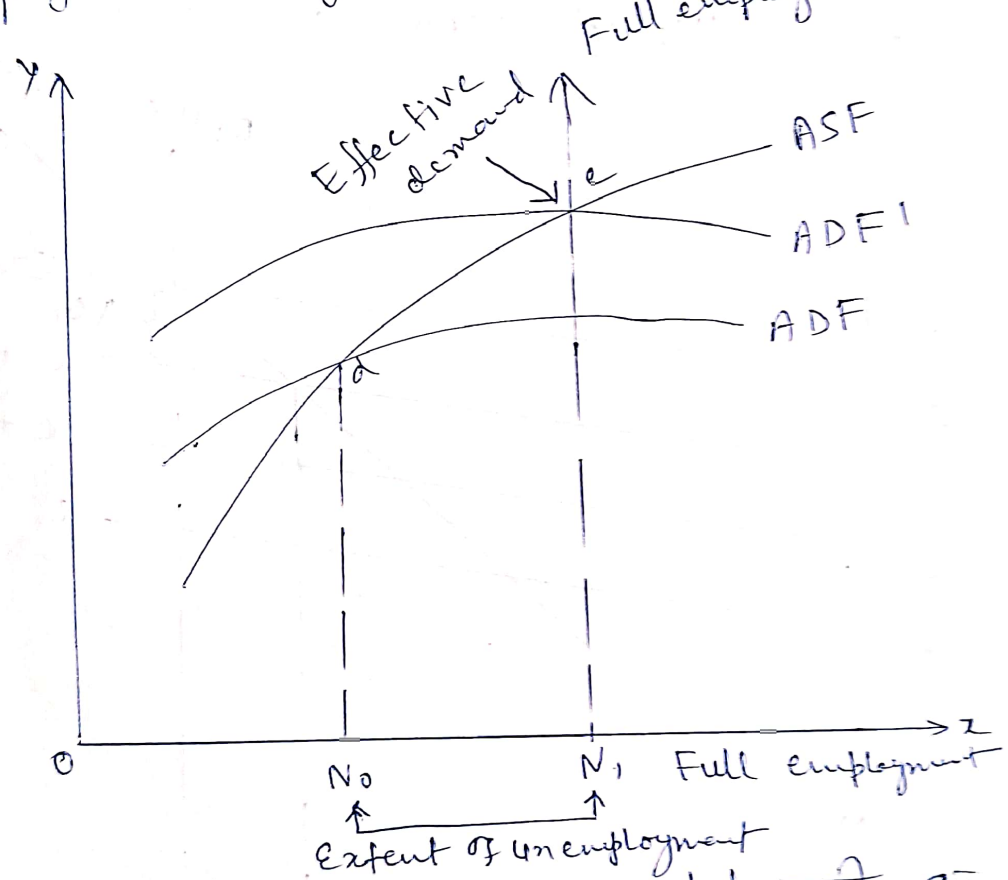

उपर के चित्र में स्पष्ट है कि बेरोजगारी का कारण effective demand में कमी है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ADF रेखा में upward shift लाकर पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

Keynes ने निवेश तथा रोजगार की व्याख्या करने के लिए Investment multiplier की व्याख्या की दिया जिसे आज हम Public

expenditure or Govt expenditure Multiplier के रूप में भी प्रदर्शित करते है —

$$K = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} \quad \text{—— (i)}$$

$$K_g = \frac{\Delta Y}{\Delta G} \quad \text{or} \quad \Delta Y = K_g \Delta G \quad \text{—— (ii)}$$

सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। जिसे हम पूर्ण रोजगार स्तरीय आय (Y_f) से प्रदर्शित कर सकते है —

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि हम अगर ΔG के बराबर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करे तब आय का स्तर Below ~~fuell~~-full employment (Y_m) से पूर्ण रोजगार आय की स्तर (Y_f) प्राप्त कर सकती है।

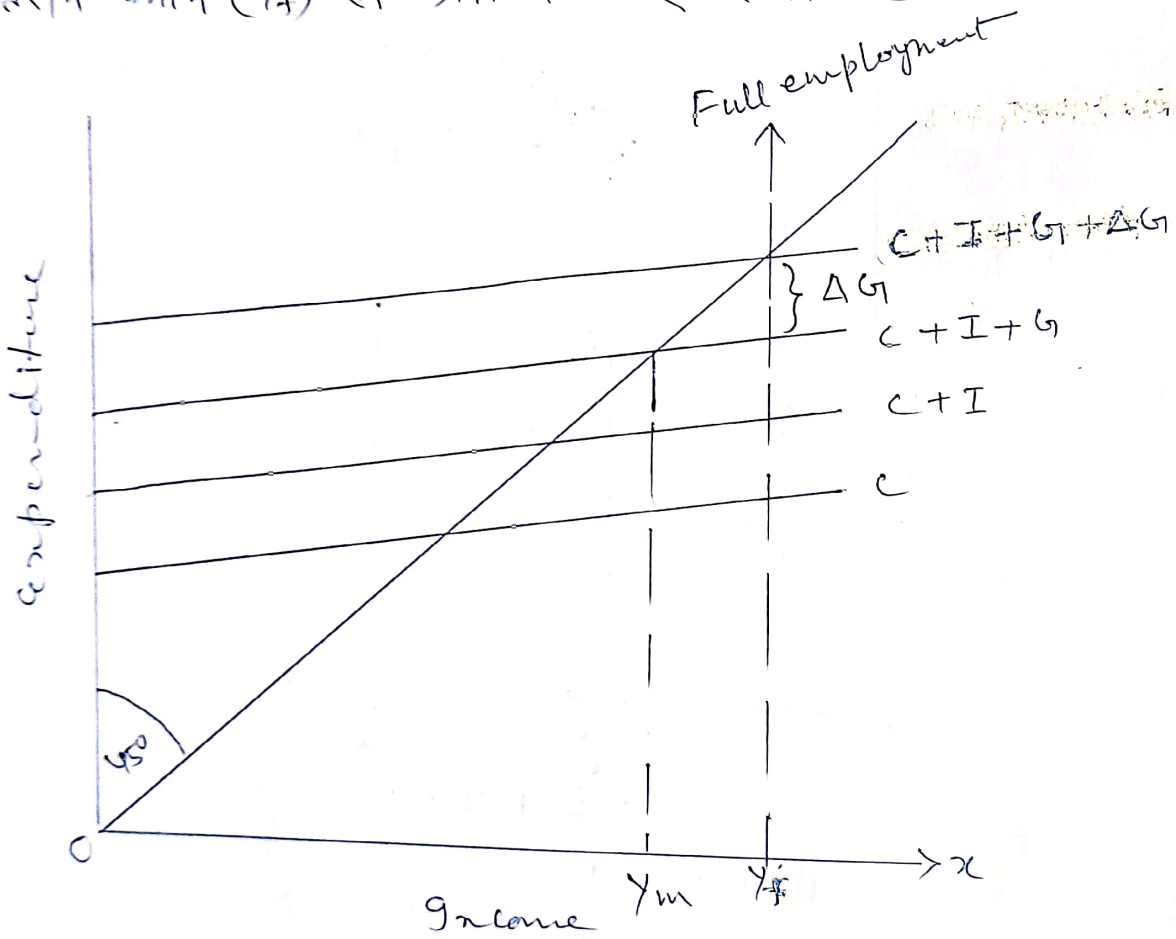

Compensatory Public Expenditure

मंदी की अवधि में किया जानेवाला सरकारी व्यय को प्रतिकारी या क्षतिपूरक व्यय (Compensatory Expenditure) कहा जाता है। क्योंकि ये व्यय वस्तुओं के प्रति लोगों की व्यक्तिगत मांगों में उत्पन्न हुई कमी को पूरा करते है। Keynes के शब्दों में, सरकारी व्यय एक संतुलन तत्व है जो कि राष्ट्रीय आय को एक निश्चित स्तर पर कायम रख सकता है। व्यवसाय-चक्र के मंदीकाल में ऐसे खर्चों में वृद्धि की जा सकती है। और जब आरोही क्रम से उठने लगे तो आर्थिक क्रियाओं का स्तर फिर उपर की जा सकती है। 1930 के ऐसे खर्चों में कमी भी की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह मंदी के समय के खर्चे किये गये थे और उनसे काफी सफलता भी मिली थी। क्षतिपूरक व्यय सार्वजनिक निर्माण योजनाओं पर Infra-structural facilities के निर्माण पर किये जाते है।

Pump-Priming Public Expenditure

पूर्ण रोजगार की प्राप्ती तथा व्यवसायिक मंदी को स्थायी रूप से रोकने के लिए सरकार को Pump-priming Public expenditure करना चाहिए यदि काफी अधिक मात्रा में सरकारी खर्च किया जाए तो उनके द्वारा मंदी से उभरने का एक ऐसा क्रम चालू किया जा सकता है जो स्वयं प्रेरणा से ही एक अनिश्चित अवधि तक अपना कार्य जारी रख सके। ऐसे ही व्यय को Pump-priming

expenditure कहते है। जैसे किसी पम्प को चालू करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी गई दिया जाता है तो वह पम्प एक निरंतर बहने वाली धारा के रूप में काफी समय तक पानी दे सकता है- इसी प्रकार यह सोचा गया कि मंदी के दिनों में सरकार एक बार कुछ व्यय खर्च कर दे तो आर्थिक जीवन का प्रवाह सदा के लिए सरलता के साथ जारी रखा जा सकता है।

इन सभी तरीकों से सरकारी व्यय के द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है परन्तु इनमें सबसे अच्छा तरीका compensatory public expenditure होती है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

Dr Sandhya Rani